B-~~2~~44
L - 54
Polity

नियोजन समितियाँ

- विकेन्द्रीत अपना कर क्षेत्रीय विषमता को न्यूनतम किया जा सकता है और भारत में उत्पन्न होने वाले नए राज्यों के मांग को हतोत्साहित किया जा सकता है।

- नियोजन समियों से यह और स्पष्ट हो जाता है कि शहरी और ग्रामीण विकास का आधार एकीकृत रूप में निर्मित किया जाएगा जिससे संसाधनों के विभाजन का निर्धारण किया जा सके तथा स्थानीय प्राथमिकता के अनुसार विकास की रणनीति बन सके।

वित्तीय स्वायत्ता

- स्थानीय स्वशासन में वित्तीय स्वायत्ता के अभाव में प्रशासनिक और राजनीतिक विकेन्द्रीकरण प्रभावित नही हो सकता। नगरपालिकाओं के लिए निम्नलिखित वित्तीय स्त्रोत हैं-

(i) नगरपालिकाओं के अपने राजस्व जो इन्हें भूमि, भवन बिजली, मनोरंजन पार्किंग से प्राप्त होते हैं।

(ii) राज्यों के करों से प्राप्त विभाजित राशि

(iii) केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं से प्राप्त राशी

(iv) राज्य सरकार के द्वारा दिये गए अनुदान

यह संयोग का विषय है कि दिल्ली नगर निगम घाटे में चल रही है जिसका यह अभिप्राय है

कि स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण का विचार असफल हो रहा है। नगरपालिकाओं के वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

(i) नगर के हाउस टैक्स, पार्किंग शुल्क, पानी और बिजली के लिए लगने वाले शुल्कों का निर्धारण एक स्वायत्त समिति के द्वारा होना चाहिए।

(ii) हाउस टैक्स के निर्धारण में आधुनिक तकनीक जैसे AI का प्रयोग करना चाहिए।

(iii) नगरनिगमों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्थानीय लोकपाल का गठन होना चाहिए।

(iv) नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों के विकास हेतु निजी फंडिंग को आकर्षित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :-

स्वशासन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक क्रान्तिकारी कदम है लेकिन इसे और प्रभावी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सौंपने की आवश्यकता है